

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 28/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा

दायरा दिनांक: 25.4.2017

अन्तर्गत धारा: 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

- 1 बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज० जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर आत्मज पीरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

... अपीलार्थी

बनाम

- 1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, कोटा।
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।
- 3 जुम्मा पुत्र ईस्माईल अंसारी जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
- 4 सुभान पुत्र ईस्माईल अंसारी जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

...रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित : श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री तेजमल जेन अभिभाषक रेस्पोंडेंट कम-3 व 4



---निर्णय---

दिनांक 11.1.2018

- 1 अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 283/2001 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज० जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर बनाम स्टेट आफ राज०, जुम्मा वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.8.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की है।
- 2 अपील के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक वाद/प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खातोली तहसील पीपल्दा में ख० नं० 495 रकबा 4 बीघा कब्रिस्तान की भूमि जो वक्फ सम्पत्ति है। जो सेटलमेंट विभाग द्वारा ख० नं० 779 की 0.04 है० तथा 780 रकबा 0.72 है० में तब्दील कर रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। सेटलमेंट के दौरान कब्रिस्तान की भूमि में से दक्षिण दिशा की भूमि को ख० नं० 778 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया तथा पुराने कब्रिस्तान की भूमि का रकबा बढ़ाकर कुछ खाली भूमि कब्रिस्तान की भूमि में शामिल कर दी गई जो मौजूदा नक्शे में स्पष्ट होती है। अतः कब्रिस्तान की भूमि को सिवायचक से निकाल कर पुनः कब्रिस्तान की भूमि दर्ज की जावे तथा जो भूमि अतिरिक्त शामिल कर दी गई उसको निकाल कर रकबा कम कर पूर्ववत् 4 बीघा 11 बिस्वा के बराबर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रार्थी का वाद निर्णय दिनांक 17.8.2016 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपील न्यायालय में इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलांत को बिना सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित किया है जो कानून न्याय एवं तथ्यों के विपरीत है। वक्त वर्णित भूमि वक्फ सम्पत्ति है जो दर्ज राजस्व रिकार्ड है। न्यायालय हाजा के पूर्ण निर्णय दिनांक 8.11.2005 प्रकरण सं० 136/2002 में दिये गये निर्देशों की पालना भली प्रकार से नहीं की गई। मौके पर कब्रिस्तान की पूर्वानुसार भूमि पूर्ण है किन्तु सेटलमेंट बाद कब्रिस्तान का स्थान परिवर्तन कर दिया गया और पूर्व में बनी हुई कब्रों को उक्त कब्रिस्तान से बाहर

कोटा सं० 283/2001

कर दिया गया है और नाकारा भूमि में चारों ओर कोट खिंचवाकर कब्रिस्तान दिखा दिया गया। जबकि कब्रिस्तान के पूर्व ख० 495 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा थी उसके बाद नाकारा जमीन मिलाकर रकबा बढ़ा दिया गया तथा कब्रिस्तान की आराजी नया रकबा 778 कायम कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि ख० नं० 778 पूर्व ख० नं० 795 का भाग है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से पत्रावली की आदेशिकाओं में कंटिंग व हेर फेर करते हुये आरबेट्रेरी करते हुये उक्त निर्णय पारित कर त्रुटि की है। रेस्प० क्रम 3 व 4 द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का पट्टा जारी करना बताया गया जो कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि का किसी के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इसकी आड़ में कब्रिस्तान की दीवार तोड़ कर कब्जा कर निर्माण अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.8.2016 निरस्त किया जावे तथा पूर्व की भांति उक्त आराजी कब्रिस्तान की भूमि कब्रिस्तान को यथास्थान दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

- 3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में प्रकट किया कि खातोली तहसील पीपल्दा में ख० नं० 495 रकबा 4 बीघा कब्रिस्तान की भूमि जो वक्फ सम्पत्ति है। सेटलमेंट विभाग द्वारा ख० नं० 779 की 0.04 है० तथा 780 रकबा 0.72 है० में तब्दील कर रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। सेटलमेंट के दौरान कब्रिस्तान की भूमि में से दक्षिण दिशा की भूमि को ख० नं० 778 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया तथा पुराने कब्रिस्तान की भूमि का रकबा बढ़ाकर कुछ खाली भूमि कब्रिस्तान की भूमि में शामिल कर दी गई जो मौजूदा नक्शों से स्पष्ट है। न्यायालय हाजा के पूर्ण निर्णय दिनांक 8.11.2005 प्रकरण सं० 136/2002 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर तथ्यों को नजरअंदाज किया है। कब्रिस्तान की भूमि का किसी के नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पट्टा धारक का कोई अधिकार नहीं है। हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया। आदेशिकाओं में कांट छंट कर हेरफेर करते हुये आरबेट्रेरी करते हुये निर्णय पारित कर त्रुटि की है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा पूर्व की भांति उक्त आराजी कब्रिस्तान की भूमि को यथावत दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।
- 5 विद्वान अभिभाषक रेस्प० क्रम-3 व 4 ने बहस में बताया कि बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ राज० जरिये मुतवल्ली द्वारा उपखण्ड अधिकारी इटावा के न्यायालय में ख० नं० 496 के संबंध में दावा पेश किया गया जिसमें पारित निर्णय दिनांक 28.8.2002 के विरुद्ध रेस्प० क्रम 3 व 4 द्वारा अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई जिसे 8.11.2005 को आंशिक रूप से स्वीकार कर स्वयं मौका देखकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड निर्देशों की पालना में मौका देख कर जेरअपील निर्णय पारित किया है। ख० नं० 496 कभी वक्फ के नाम नहीं रहा है। ख० नं० 495 वक्फ की सम्पत्ति है। माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट द्वारा भी तनकी सं० 5 में वक्फ का होना नहीं माना है। आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं तथा अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।
- 6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया। रेस्प० अभि० ने अपीलांत द्वारा शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है तथा ना ही खण्डन में कोई साक्ष्य सबूत पेश किये हैं। अतः न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 7 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजात एवं जेरअपील निर्णय का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांत द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ दस्तावेजात, निर्णय दिनांक 2.4.11 मि० सं० 80/02 न्यायालय एडीजे क्रम-5, आर्डर आफ दी हाई कोर्ट जयपुर अपील नं० 4270/06 दिनांक 23.3.2012, पट्टा दिनांक 25.12.74 ग्राम पंचायत खातोली, इकरारनामा दिनांक 25.1.02 पेश कर सुसंगत दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिये जाने का

अनुरोध किया। प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात के अवलोकन तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन उपरात प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तावेजात निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण मे पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं० 136/02 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान जुम्मा, सुभान बनाम बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज० जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर पुत्र पीरमोहम्मद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 अनुसार उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि "वे इस प्रकरण मे स्वयं मौका देखकर राजस्व अभिलेखो का भली प्रकार अवलोकन कर विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करे। इस प्रकरण मे वक्फ बोर्ड एक पक्षकार है तथा वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति व्यापक जनहित की सम्पत्ति है अतः पूर्ण संवेदना के साथ यह सुनिश्चित किया जावे कि ख० नं० 496 क्या पूर्व मे आबादी भूमि का भाग था तथा अपीलार्थी जुम्मा के द्वारा खरीदी गई भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार था इन सभी तथ्यो का मौके पर जांच एवं निरीक्षण कर प्रकरण मे नये सिरे से निर्णय किया जावे।" जेरअपील निर्णय दिनांक 17.8.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील सं० 136/02 मे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 मे दिये गये उक्त रिमांड निर्देशो की पालना का अभाव रहा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही माना जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय 17.8.2016 अपास्त किया जाता। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को, न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व प्रकरण अपील संख्या 136/02 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान जुम्मा, सुभान बनाम बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज० जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर पुत्र पीरमोहम्मद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 मे दिये गये दिशा निर्देशो का अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

8 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा मिसल सं० 283/2001 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज० जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर बनाम स्टेट आफ राज०, जुम्मा वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 17.8.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 136/02 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान जुम्मा, सुभान बनाम बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राज० जरिये मुतवल्ली मोहम्मद अकबर पुत्र पीरमोहम्मद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 8.11.2005 मे दिये गये दिशा निर्देशो का अवलोकन कर पुनः विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करें।

9 निर्णय आज दिनांक 11.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा